बाल विकास योजना के उदेश्य, सेवायें तथा उसके समक्ष आने वाली चुनौतियाँ और सुधार के संदर्भ का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीति सिंह
शोधार्थी, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

डॉ0 छवि वर्मा
शोध निर्देशिका, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सार–

देश में बाल विकास के व्यापक ढांचे को शुरू करने की दृष्टि से, एकीकृत बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) को देश के चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। एक बच्चे के व्यक्तित्व में समग्र प्रगति करने में पायलट जिलों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के तुरंत बाद, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य देश में बच्चों के विकास का ऐसा ढांचा उपलब्ध कराना रहा है कि बच्चे के विकास में पोषण के साथ–साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में कोई कमी न रहे। धीरे–धीरे, यह कार्यक्रम बाल कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा जिसमें देश का कोई भी हिस्सा कार्यक्रम के दायरे से बाहर नहीं रहा। इस कार्यक्रम के तहत, पुरुषों, महिलाओं और सामग्रियों का एक व्यापक ढांचा निर्धारित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई अक्षमता न हो जिससे कि इस कार्यक्रम से निकलने वाले परिणामों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न न हो। देश में बाल कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों को भव्य तरीके से लागू किए जाने के बावजूद, बच्चों के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं की स्थिति में वांछनीय परिवर्तन लाने में उनकी प्रभावशीलता एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। यद्यपि बाल विकास नीतियों और कार्यक्रमों के विचार और कार्यप्रणाली के मूल्यांकन पर अधिक आधिकारिक कार्य नहीं किया गया है आम तौर पर यह समझा जाता है कि इन कार्यक्रमों के वैचारिक अभिविन्यास के साथ–साथ व्यावहारिक कार्यान्वयन में पर्याप्त कमी रही होगी। यद्यपि योजनाओं को अखिल भारतीय आधार पर लागू किया जाता है, लेकिन कार्यक्रमों का मूल तर्क और औचित्य पूरे देश में समान रहता है। इनमें से आईसीडीएस देश में बाल कल्याण की सबसे प्रमुख योजना है।

प्रस्तावना–

आई0सी0डी0एस0 की उत्पत्ति देश में एक बच्चे की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की देखभाल करने के पिछले कई प्रयासों की विफलताओं में देखी जा सकती है। सच तो यह है कि आजादी के बाद से ही भारत सरकार के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारों का लगातार यह प्रयास रहा है कि बच्चों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों का ध्यान रखा जाए क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन सरकार की ओर से एक स्पष्ट दृष्टि और कार्य योजना के अभाव में, बाल विकास और कल्याण नीतियां खंडित होने के साथ–साथ संकीर्ण भी रहीं। उदाहरण के लिए, शुरुआती दिनों में जब देश में बाल मृत्यु दर खतरनाक रूप से अधिक थी, सरकार ने बच्चे के स्वास्थ्य के मुद्दों की देखभाल के संदर्भ में देश में बाल विकास और कल्याणकारी नीतियों की अवधारणा के बारे में सोचा। लेकिन बहुत जल्द ही सरकारी और अन्य एजेंसियों दोनों की समीक्षा रिपोर्ट और साथ ही सरकार के अन्य नीतिगत

मूल्यांकन में यह बताया गया कि स्वास्थ्य बाल कल्याण की प्रमुख चिंता होने के बावजूद, इसे सरकार की एकमात्र मुख्य चिंता के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

इसी तरह, लंबे समय तक, देश में बाल कल्याण और विकास की अवधारणा बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में की गई थी। वास्तव में जब देश की विकासात्मक प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा रहा था, तब नीति–निर्माताओं ने यह सोचा था कि देश की वृद्धि और विकास की दर को तब तक तेज नहीं किया जा सकता जब तक कि देश के मानव संसाधन शैक्षिक कौशल और कौशल से सुसज्जित न हों। विकास के अन्य वांछनीय पैरामीटर। यह ध्यान रखना काफी दिलचस्प है कि उस समय, लोगों के लिए विकास के बुनियादी मानदंड स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी जरूरतों तक ही सीमित थे, जिससे लोगों की अन्य जरूरतें पूरी तरह से खत्म न होने पर हाशिए पर आ गईं। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ज़रूरतें अन्य विकासात्मक ज़रूरतों से आगे निकल गई हैं और इसलिए, अगर सभी नहीं तो अधिकांश, योजनाओं में विकासात्मक प्राथमिकताएँ स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों के इर्द–गिर्द घूमती हैं। लेकिन विकास का ऐसा परिप्रेक्ष्य किसी बच्चे के मामले में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी छोटी उम्र में निहित विशिष्ट और अजीबोगरीब ज़रूरतें और ज़रूरतें थीं।

हालांकि लंबे समय तक, देश में बच्चों के विकासात्मक अनिवार्यताएं अनिश्चितता और प्रयोग के भंवर में बनी रहीं, वास्तव में नीति निर्माताओं पर नए इनपुट और अंतर्दृष्टि के मद्देनजर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का दायित्व महसूस किया गया। एक बच्चे की वृद्धि और विकास पर राष्ट्रीय चिंता के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दोनों द्वारा प्रदान किया गया। इस समय के दौरान, बाल कल्याण से संबंधित बुनियादी तर्क बच्चों की बुनियादी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव के इर्द–गिर्द घूमता था। उनकी वृद्धि और विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम। इस संदर्भ में, अफ्रीकी देशों में बच्चों की दुर्दशा से पथप्रदर्शक इनपुट प्राप्त हुए, जहां बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से इस तरह से पीड़ित पाया गया कि उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति ने उन्हें किसी भी तरह की बीमारी के लिए जाने की अनुमति नहीं दी। जीवन के अन्य सार्थक उद्यम। दूसरे शब्दों में, बच्चे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की इतनी बहुलता से पीड़ित पाए गए कि उनके जीवन के अन्य पहलू नीति निर्माताओं के लिए अप्रासंगिक प्रतीत हुए। इसने भारत में नीति निर्माताओं के लिए देश में बाल कल्याण नीति को फिर से शुरू करने और इस संबंध में एक समग्र नीति बनाने के लिए सही संदर्भ प्रदान किया।

उद्देश्य–

आईसीडीएस आमतौर पर 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के कल्याण से संबंधित है। इसे निश्चित उद्देश्यों के एक सेट के साथ तैयार किया गया है, जिसकी पूर्ति से देश के बच्चों को घेरने वाली विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने में काफी हद तक मदद मिलने की संभावना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में परिभाषित आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाना है। योजना का यह उद्देश्य देश की लंबे समय से चली आ रही समस्या के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसमें बहुत कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कई बीमारियों और विकारों से पीड़ित होते थे। उदाहरण के लिए, पोलियो हुआ करता था। देश के विकासात्मक विमर्श में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य हस्तक्षेप और किसी भी हितधारक के समर्थन के अभाव में, यह कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे प्रमुख स्वास्थ्य खतरों में से एक है। नतीजतन, बड़ी संख्या में बच्चे पोलियो वायरस से संक्रमित होने

की स्थिति में जीवन भर के लिए पीड़ित हो जाते थे और जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिवार या अन्य लोगों पर निर्भर रहते थे।

स्वास्थ्य और पोषण के अलावा, आई0सी0डी0एस0 का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए एक ठोस पृष्ठभूमि प्रदान करना रहा है। इसे देश में बच्चों के लिए पिछले विकासात्मक डिजाइन में लापता कड़ियों में से एक के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि नीति निर्माताओं को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ज़रूरतें भी हो सकती हैं जिनकी पूर्ति उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि बच्चे की शारीरिक और अन्य आवश्यकताओं के लिए। इसके अलावा, यह योजना देश में रुग्णता, मृत्यु दर और कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी के उद्देश्य को भी प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार, आईसीडीएस को बच्चों के जीवन की छोटी उम्र में सामना की जाने वाली बहुआयामी चुनौतियों के मद्देनजर सही मायने में पैकेज डील के रूप में देखा गया है। आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली सेवाओं का पैकेज समाज के साथ–साथ सरकार की ओर से सबसे प्रभावी हस्तक्षेप साबित हो सकता है जो न केवल उनके विकास के दबाव वाले मुद्दों और चुनौतियों से दूर होने में मदद कर सकता है बल्कि उन्हें एक बनने में भी मदद कर सकता है। समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति।

आई0सी0डी0एस0 का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में बाल कल्याण की खोज में विभिन्न हितधारकों की ओर से समन्वय और नीति कार्यान्वयन की अधिकतम संभव सीमा को प्राप्त करना है। वास्तव में, बाल अधिकार, बाल कल्याण और बाल विकास के संरक्षण और संवर्धन में बहुत सारी एजेंसियां, अभिनेता, हितधारक और व्यक्ति लगे हुए हैं। लेकिन उनके बीच उचित समन्वय के अभाव में उनकी पहल प्रभावित होती थी। इस प्रकार, आई0सी0डी0एस0 उनके बीच यथासंभव उचित समन्वय लाने का प्रयास करता है। अंत में, आई0सी0डी0एस0 का उद्देश्य उचित शिक्षा और बच्चे की जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना भी है। इस प्रकार, आई0सी0डी0एस0 की अवधारणा बहुत सारे उद्देश्यों के साथ की गई है, जिनकी उपलब्धि निश्चित रूप से देश में बाल कल्याण और बाल विकास का सर्वोत्तम संभव माहौल बनाने में मदद करेगी। लेकिन इस संबंध में विचारणीय प्रश्न योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इस तरह से आता है कि ये उद्देश्य लघु और साथ ही दीर्घ अवधि दोनों में वास्तव में प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं।

संक्षेप में, आईसीडीएस के उद्देश्य तीन तरह से अद्वितीय हैं। एक, वे अतीत में इस मुद्दे के प्रति खंडीय दृष्टिकोण की तुलना में बच्चों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए, केवल छह साल की छोटी उम्र में, एक बच्चा स्वस्थ जीवन और उचित पोषण की पूर्ण आवश्यकता के अलावा और कुछ नहीं चाह सकता है जो उसे स्वास्थ्य और फिटनेस में परिपूर्ण रख सके। दो, आईसीडीएस में बच्चे के समग्र विकास में सबसे मूल्यवान इनपुट के रूप में मां के स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और शोधों में यह बात संदेह से परे साबित हो चुकी है कि छह साल की उम्र तक बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह से मां के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसलिए मां के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की लापरवाही बच्चे की भलाई के लिए प्रशंसनीय प्रस्ताव नहीं बन सकती। अंत में, आई0सी0डी0एस0 का उद्देश्य सभी हितधारकों, अभिनेताओं और व्यक्तियों के साथ–साथ बच्चों की भलाई में शामिल एजेंसियों को एक सामान्य मंच पर लाना है ताकि उनमें सामान्य उद्देश्य के साथ समन्वित और ठोस कार्रवाई की भावना पैदा की जा सके। बच्चे का कल्याण।

आईसीडीएस के तहत सेवाएं–

यह देखते हुए कि आई0सी0डी0एस0 को एक पैकेज डील के रूप में पेश किया जाता है, इसमें कई महत्वपूर्ण सेवाएँ शामिल हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की गारंटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इसमें कई सहायक और सहायक सेवाएं शामिल हैं, आईसीडीएस के तहत दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं छह हैं। ये सेवाएं संचयी रूप से एक बच्चे के व्यक्तित्व के लगभग सभी आवश्यक या अपरिहार्य घटकों से संबंधित हैं, यदि किसी बच्चे को उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास की गारंटी दी जाती है, तो इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, जैसा कि स्पष्ट है, आईसीडीएस की प्राथमिक चिंता 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूरक पोषण का प्रावधान है। इस तरह के पोषण पूरक को बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन माना जा सकता है। खाद्य पदार्थों में पर्याप्त पोषण सामग्री के साथ–साथ देश में अधिकांश लोगों के भोजन के विकल्प। आईसीडीएस बच्चों को पूरक पोषण सहायता प्रदान करके बच्चों के पोषण सेवन में कमी को पूरा करने में मदद करता है।

आई0सी0डी0एस0 के तहत दी जाने वाली एक अन्य प्रमुख सेवा देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों को पूर्वस्कूली गैर–औपचारिक शिक्षा देना है। पूर्वस्कूली गैर–औपचारिक के महत्व को इस तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा विकासशील देशों में बच्चों के लिए समग्र विकास पैकेज की रीढ़ हैं जहां इन देशों में स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। जहां तक भारत का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में देश द्वारा तेजी से किए गए विकास के बावजूद देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की संख्या अभी भी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। इसलिए, आईसीडीएस शिक्षा के उचित समर्थन के साथ बच्चों को स्वास्थ्य पूरक की पूर्ति करना चाहता है। पूर्वस्कूली गैर–औपचारिक के हिस्से के रूप में, आईसीडीएस केंद्र बच्चों को उनके शुरुआती चरणों में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा प्रदान करते हैं।

जिंदगी। इस प्रकार आईसीडीएस वास्तव में स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बच्चों के समग्र व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के लिए समग्र समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सेवाओं के इस दुर्लभ संयोजन ने वास्तव में देश में चमत्कार किया है, हालांकि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कई अन्य प्रयास भी किए गए हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जरूरतों और आवश्यकताओं के लिए ठोस समर्थन और पूरक प्रदान करने के अलावा, आईसीडीएस बच्चों के माता, पिता, अभिभावकों और संरक्षकों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के लिए सार्वजनिक समर्थन प्रदान करना चाहता है। वास्तव में, एक बच्चे के समग्र विकास में स्वास्थ्य और शिक्षा की जीवन शक्ति के संबंध में लोगों के बीच ज्ञान और जागरूकता के पर्याप्त स्तर की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा आईसीडीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक प्रतीत होता है। . लेकिन अभिभावकों के विवेक के लिए अपरिहार्य करने योग्य चीजों को न छोड़ने के लिए, आईसीडीएस भी 0 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को टीकाकरण की सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें कई स्वास्थ्य खतरों, बीमारियों से बचाया जा सके। बच्चों के लिए अन्य के बीच संक्रमण। टीकाकरण के कार्य को देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है, जो कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों की एक विशाल श्रृंखला और बच्चों के लिए अपंग कारक के रूप में कार्य करने वाले संक्रामक रोगों की चपेट में आता है। जीवन भर के लिए लाचार कर देना।

आईसीडीएस के रूब्रिक के तहत दी जाने वाली दो अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं हैं। दुनिया में स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य ढांचे के बदलते प्रतिमान के साथ, निवारक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है, जितनी कि किसी बीमारी के लिए प्रदान किए जाने वाले उपचार की। इसलिए, आईसीडीएस को एक आईसीडीएस केंद्र के दायरे में आने वाले सभी बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी खतरे से पीड़ित नहीं हैं, जिनका उपचार किसी भी समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। उनके जीवन का बाद का चरण। इसके अलावा, आईसीडीएस उन स्वास्थ्य मुद्दों के लिए बच्चों को रेफरल सेवाएं प्रदान करना चाहता है जिनका स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में इलाज नहीं किया जा सकता है। संकल्पनात्मक रूप से, रेफरल सेवाएं उन सेवाओं के सेट को संदर्भित करती हैं, जहां गैर–विशिष्ट या स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में एक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने वाला डॉक्टर स्वास्थ्य देखभाल के एक उन्नत केंद्र में आगे के इलाज के लिए रोगी के मामले को संदर्भित करता है। आईसीडीएस के हिस्से के रूप में रेफरल सेवाओं ने वास्तव में गंभीर बीमारियों से पीड़ित बहुत से बच्चों को उन्नत और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज कराने में मदद की है।

चुनौतियां और सुधार–

बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रमुख कार्यक्रम होने के नाते, आईसीडीएस ने निस्संदेह अपने लंबे काम के वर्षों में कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आईसीडीएस के सामने बुनियादी मुद्दे तब उभरने लगे जब यह योजना देश के विभिन्न हिस्सों में लागू होने लगी। ये मुद्दे और चुनौतियाँ बहुविध रही हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के समूहों से निकली हैं। उदाहरण के लिए, समाज के कई सामाजिक और आर्थिक समूहों से जुड़ा सामाजिक कलंक इन समूहों के बच्चों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आईसीडीएस केंद्रों में जाने से रोकता था। यहां तक कि जब उन्हें वास्तव में आईसीडीएस केंद्रों तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी, तब भी कई बार ऐसे केंद्रों पर काम करने वाले लोग उन्हें बिना शर्त और बेहिचक तरीके से संभावित मदद और समर्थन नहीं देते थे। इनके अलावा कई अन्य चुनौतियां भी सामने आईं। कार्यक्रम, नीतियों, उनके कार्यान्वयन, वित्त, जनशक्ति, रसद और कई अन्य संबंधित चीजों के परिप्रेक्ष्य जो इस कार्यक्रम के कुशल और प्रभावी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक के रूप में कार्य करते हैं।

आईसीडीएस के विभिन्न पहलुओं के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को सरकारी एजेंसियों के बारे में पता है, जो उन्हें जब भी संभव हो उचित तरीके से कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आईसीडीएस कार्यक्रम के भीतर कमियों को दूर करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मद्देनजर किए गए, जिसमें प्रभावी तरीके से इन सभी खामियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने की मांग की गई थी। इस संबंध में सरकारी प्रयास समग्र रूप से और अच्छी तैयारी के साथ किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचारात्मक उपाय योजना के सफल संचालन पर आवश्यक प्रभाव डालने में विफल न हों। दूसरे शब्दों में, कार्यक्रम प्रबंधकीय और संस्थागत के बहुत विविध क्षेत्रों से संबंधित सरकारी प्रयास। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार के उपाय झूठे वादे साबित न हों, योजना ने वित्तीय संसाधनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए ताकि इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह, बारहवीं योजना आईसीडीएस के विकास में एक महत्वपूर्ण

मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि इसने देश में वर्षों से आईसीडीएस के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को दूर करने की मांग की।

आईसीडीएस के भंवर में किए गए सुधारों का पहला सेट योजना की कार्यक्रम संबंधी प्रकृति से संबंधित है। इसने आईसीडीएस में बाल कल्याण के बुनियादी कार्यक्रम के रूप में खामियों की पहचान करने की कोशिश की और ऐसी खामियों को दूर करने के लिए उचित उपाय विकसित किए। इस संबंध में, गांव के आसपास के सभी हितधारकों को स्वास्थ्य, पूरक पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार की सहायक गतिविधियों के लिए पहले केंद्र के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के साथ शुरुआत की गई थी। केंद्र के इस तरह के पुनर्नामकरण का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी मूल्यवान हितधारक अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सूचित किए बिना न रहे जिसे बाद में पूरक पोषण के साथ सुधारा जा सके। आईसीडीएस के कार्यक्रम संबंधी सुधारों में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में शामिल लोगों को केंद्र में स्थित भवन की बढ़ी हुई लागत, मौद्रिक या अन्य प्रकार के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे भी शामिल थे, श्रमिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपायों को मजबूत करना उपयुक्त नवीनतम तकनीक और कौशल ताकि वे बच्चों के लिए सर्वोत्तम संभव सहायता प्रदान कर सकें।

प्रोग्रामेटिक सुधारों को विभिन्न प्रकार के प्रबंधन सुधारों द्वारा पूरक किया गया था जो कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों के लिए सेवा वितरण में सुधार के मूल में गए थे। इन सुधारों की शुरुआत विकेंद्रीकृत योजना और योजना की प्रोग्रामिंग के साथ इस तरह से हुई कि इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किए जाने वाले संबंधित गतिविधियों का पूरा सेट स्थानीय आबादी की जिम्मेदारी बन जाता है। साथ ही, सरकार ने भी निर्धारित किया न केवल इसके लिए पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र स्थापित करके बल्कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की ऑनलाइन आपूर्ति और ट्रैकिंग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे नवीनतम तकनीकी नवाचारों का सहारा लेकर योजना की जवाबदेही और जिम्मेदारी तंत्र में सुधार करना। इसी प्रकार, सरकार के प्रयास भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक संभव उपयोग पर जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के निष्पादन में अक्षमता का कोई कदाचार दिखाई न दे। सरकार ने विभिन्न हितधारकों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को इस तरह से ठीक करने का भी प्रयास किया कि उन्हें अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तरीके से पुरुषों और सामग्रियों को पुनर्नियोजित करने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों।

आईसीडीएस के दायरे में किए गए सुधारों का एक प्रमुख जोर उन प्रशासनिक उपायों की प्रकृति में रहा है जो कार्यक्रम की कार्यकुशलता को सुव्यवस्थित करने की नींव रख सकते हैं। मितव्ययिता, दक्षता और कार्यक्रम की प्रभावशीलता के मुद्दों से संबंधित प्रशासनिक सुधारों का मूल पैरामीटर। यह देखते हुए कि आईसीडीएस एक पूंजी गहन कार्यक्रम रहा है जिसमें बड़ी संख्या में घटकों की भागीदारी से योजना पर खर्च बढ़ता है कई गुना, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की लगातार चिंता रही है कि योजना के कार्यान्वयन में लागत प्रभावशीलता बनी रहे। योजना की दक्षता के संबंध में मिलान उपायों से योजना की लागत प्रभावशीलता को और मजबूत किया गया है। प्रशासनिक सुधार का मूल आधार यह था कि योजना के कुशल कार्यान्वयन से स्वतः ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि निधियों के निहित अपव्यय और दुरुपयोग को कम किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे उपायों को योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार की मुख्य चिंता बच्चों और उनकी माताओं के कल्याण को सुनिश्चित करना था।

कुल मिलाकर, आई0सी0डी0एस0 के विभिन्न पहलुओं में सुधार के सरकारी प्रयास एक समग्र उपाय रहे हैं जिसमें सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि योजना के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की कमी नहीं है जो इसे सफेद बनाने के अलावा इसकी प्रभावशीलता से समझौता कर सके। हाथी। इसलिए इसने योजना के पीछे मूल विचार के साथ योजना के विभिन्न प्रकार के दोषों और समस्याओं की पहचान करना शुरू किया और लगभग सभी पहलुओं को कवर करने के लिए घूम रहा था जिनकी योजना के कार्यान्वयन में एक कुशल और प्रभावी भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तौर–तरीका। वास्तव में, सुधार उपायों की प्रक्रिया में, सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत दिखाई दी कि सुधार के उपाय योजना के अंतिम उद्देश्य से समझौता नहीं करते हैं। इसलिए जहां तक इस योजना में समग्र सुधारों का संबंध है, यह एक सतर्क मार्ग पर चला। फिर भी, योजना के सुधारों ने वास्तव में यह सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय किया है कि यह योजना एक ओर सरकार के लिए अस्थायी हाथी नहीं बन गई है और यह वास्तव में इसके लिए समग्र रूप से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। एक प्रकार का विचलन।

निष्कर्ष–

आई0सी0डी0एस0 को भारत में बच्चों के समग्र कल्याण और कल्याण के लिए सरकार की प्रमुख योजना के रूप में देखा जा सकता है। यह योजना सरकारी हलकों में इस अहसास के मद्देनजर शुरू की गई थी कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ–साथ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की देखरेख की लागत राष्ट्रीय खजाने पर भारी पड़ रही है और इसे हासिल किया जा सकता है। कुछ रणनीतिक उपायों को शुरू करके। इस प्रकार, आईसीडीएस एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू हुई जिसे जल्द ही देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया गया। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं ऐसी सेवाओं की अधिकता हैं जो देश में बच्चों और उनकी माताओं के उचित स्वास्थ्य और पोषण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि वर्षों से, यह योजना देश में मानव विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की ओर से एक सफल हस्तक्षेप रही है, यह कई महत्वपूर्ण मुद्दों और अंतरालों से पीड़ित रही है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- ढींगरा, आर. और शर्मा, आई., 'एसेसमेंट ऑफ़ प्रीस्कूल कंपोनेंट ऑफ़ आईसीडीएस स्कीम इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट', ग्लोबल जर्नल ऑफ़ ह्यूमन साइंस, 11(6), 2006, पीपी. 13–18।
- इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 41, नहीं। 34, 2006, पीपी 3706–3715।
- काकर, सुधीर, 'इन्सेस्ट्युअस एब्यूजः ए कमेंट', कलि का युग, 1(1) नवंबर 1996. पृ. 15–16।
- बिष्ट, रचिता, 'हू इज़ ए चाइल्डः द एडल्ट्स पर्सपेक्टिव विदिन एडल्ट–चाइल्ड रिलेशनशिप इन इंडिया', इंटरपर्सोना, 2 (2), 2008, पीपी. 145–156
- थोराट, एस. और सदाना, एन., डिस्क्रिमिनेशन एंड चिल्ड्रेन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस इन इंडिया, आईडीएस प्रकाशक, नई दिल्ली, 2002
- विरानी, पिंकी, बिटर चॉकलेट – भारत में बाल यौन शोषण, पेंगुइन बुक्सः भारत, 2000
- हडसन, पी., और मैकेंजी, बी. 'एक्सटेंडिंग एबोरिजिनल कंट्रोल ओवर चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेजः द मैनिटोबा चाइल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव', कैनेडियन रिव्यू ऑफ सोशल पॉलिसी, 51, 2003, 49–66।

- श्रीनिवास, एम.एन., मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, न्यू बुक कंपनी, बॉम्बे, 1998
- सुसान, मैथ्यूज, किशोर न्याय पर राष्ट्रीय परामर्श की एक रिपोर्ट, बैटर प्रकाशन, चेन्नई, 2001
- डे, पार्थ और नंदिता चट्टोपाध्याय, 'बाल विकास पर कुपोषण का प्रभावः भारत के एक पिछड़े जिले से साक्ष्य', नैदानिक महामारी विज्ञान और वैश्विक स्वास्थ्य, 72 (2), पीपी. 42–68
- डेवी, ए., डेवी, एस., और दत्ता, यू., 'दिल्ली में शहरी आईसीडीएस ब्लॉकों में सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में धारणा', इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 52(3), 1998, पीपी. 156–158।
- देसाई, एस., वनमैन आर., और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली, भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस), 2005, एन आर्बर, एमआईः इंटर–यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिसर्च, 2006, पीपी। 92–109
- लाल, बी. सुरेश, 'चाइल्ड मैरिज इन इंडियाः फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, मई 2015, पीपी. 29–37

PC
PARTH COMPUTERS